Title: Demand to provide funds, food and drinking water to the drought affected areas of Gujarat and to direct the states to pay remaining amount of the Sardar Sarovar Project.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अंदर पिछले दो-तीन सालों से सूखा पड़ा हुआ है। अपेक्षित बरसात नहीं हुई है। परिणामस्वरूप सारे किसान परेशान हैं, उनकी सारी फसल नट हो गई है और मवेशियों की क्षति हो रही है, क्योंकि उनको चारा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा पीने के पानी की भी असुविधा है। गुजरात में साल में 120 दिन कम से कम बारिश होती है, लेकिन पिछले साल केवल 26 दिन बारिश हुई। 1998 में 114 प्रतिशत बरसात हुई थी, लेकिन 1999 में केवल 73 प्रतिशत हुई। परिणामस्वरूप खरीफ की फसल को काफी क्षति पहुंची है। इसके साथ-साथ मूंगफली की फसल को भी हानि हुई है। बाजरा, ज्वार, चावल और कपास का जितना उत्पादन होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। गुजरात में अनावृटि के कारण 21 जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। कुल 175 तहसील, 5575 गांव अनावृटि की चपेट में हैं। 5463 गांवों में चार से छ आनावारी से भी कम है । चारे की कमी है। कुल मिलाकर 11020 गांव सूखे की चपेट में हैं। गुजरात सरकार ने सूखे से निपटने के लिए अपना मास्टर प्लान बनाया है, जिससे पशुओं को चारा, लोगों को पानी और राहत कार्य चला कर लोगों को रोजगार दिया जा सके। जिस तरह केन्द्र सरकार ने पहले चारे और पानी के लिए वैगन उपलब्ध कराए थे, उसी तरह फिर से यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा विशेा कोा से वहां के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति मंत्रालय द्वारा वहां सूखे से प्रभावित लोगों को 2 रू. किलो 3 रू. किलो गेहूं और चावल देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की हमारी राशि जो हमारे राज्य मध्य प्रदेश पर 786 करोड़ रुपए बकाया है, महाराट्र पर 195 करोड़ रुपए तथा राजस्थान पर 290 करोड़ रुपए बकाया है, वह राशि भारत सरकार द्वारा इन राज्यों को आदेश देकर अविलम्ब गुजरात को दिलाई जाए, जिससे हम सूखे से राहत पा सकें।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ) : अध्यक्ष महोदय, जो बातें रतिलाल जी ने कही हैं, मैं उनको नहीं दोहराऊंगी। गुजरात में यह दूसरा साल है, जब वहां अकाल की परिस्थिति पैदा हुई है। 10431 गावं इससे प्रभावित हैं। मैं केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करती हूं कि जो भी गुजरात सरकार की मांग है, वह पूरी की जाए। जैसे कृाि मंत्रालय ने पिछले साल व्यवस्था की थी इस साल भी करे। हमारी नर्मदा योजना के राजस्थान, महाराट्र और मध्यप्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों पर जो बकाया है हमारा, वह हमें तत्काल दिलाया जाए।

श्री पी.एस. गढवी (कच्छ) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विाय पर आज नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम नहीं है।